संख्या-44/2026/I/1378744/2026/11-4099/24/2023

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 29 जून, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद-सिद्धार्थनगर में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-स0नि0-सिद्धार्थनगर-कार्यालय निर्माण/2026-27/172/राज्य कर, दिनांक 15.06.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-सिद्धार्थनगर में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत पूंजी लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-32-सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष परियोजना की अनुवर्ती किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-459/11-4-2024/-1764670 दिनांक 30.12.2024 द्वारा जनपद-सिद्धार्थनगर में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रु0 649.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रु0 320.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। पुनः शासनादेश संख्या-39/11-4-2025-1764670 दिनांक 06.03.2025 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा पुनरीक्षित आंकलित लागत रु0 841.75 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। शासनादेश संख्या-21/2026/I/1278131/2026/11-4099/24/2023 दिनांक 24.03.2026 द्वारा परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रु0 100.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। इस प्रकार परियोजना हेतु अब तक कुल रु0 420.00 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है तथा रु0 421.75 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद-सिद्धार्थनगर में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य** हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा पुनरीक्षित लागत रु0 841.75

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत पूंजीपक्ष के लेखाशीर्षक 4059-01-051-32-सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्रावधानित धनराशि में से प्रश्नगत परियोजना हेतु **तृतीय किश्त** के रूप में **रु0 420.875 लाख (रूपये चार करोड़ बीस लाख सत्तासी हजार पॉच सौ मात्र)** की वितीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एंव प्रस्तावित प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि प्रशासकीय विभाग के सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

2. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, गोरखपुर जोन, गोरखपुर यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य पूर्व में न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, गोरखपुर जोन, गोरखपुर/कार्यदायी संस्था की होगी।

4. आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

7. परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-39/11-4-2025-1764670 दिनांक 06.03.2025 तथा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,20,87,500 (रुपये चार करोड़ बीस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 4059010513200 सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर गोरखपुर जोन, गोरखपुर ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
8. सम्बंधित कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा आयुक्त राज्य कर उ0प्र0।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in